नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 138
दि. 21.02.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

केंद्रीय सहायता के इंतजार में बाढ़ पीड़ित किसान और गांव

(जीएनएस)। मुंबई। पिछले वर्ष हुई मूसलधार बारिश और भीषण बाढ़ ने महाराष्ट्र के हजारों परिवारों की जिंदगी को गहरे संकट में डाल दिया। खेतों में तैयार खड़ी फसलें देखते ही देखते पानी में समा गईं, घरों की दीवारें दरक गईं, पशुधन बह गया और ग्रामीण बुनियादी ढांचा बुरी तरह चरमरा गया। खासतौर पर मुंबई सहित कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई जिलों में हालात इतने गंभीर थे कि सामान्य जनजीवन लंबे समय तक पटरी पर नहीं लौट सका। आपदा के महीनों बाद भी प्रभावित किसान और ग्रामीण परिवार राहत की बाट जोह रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई केंद्रीय सहायता पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो सका है।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत केंद्र सरकार से 29,781.66 करोड़ रुपये की सहायता का विस्तृत प्रस्ताव दिसंबर के पहले सप्ताह में भेजा था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित किसानों, ग्रामीण परिवारों और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करना था। हालांकि प्रस्ताव भेजे जाने के बाद से कई दौर की समीक्षा और पत्राचार हुआ है, लेकिन अब तक अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है, जिससे राहत कार्यों की गति पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है।

राहत एवं पुनर्वास विभाग के आकलन के अनुसार, इस आपदा का सबसे गहरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा। लगातार बारिश और बाढ़ के कारण खेतों में जलभराव हो गया, जिससे फसलों की जड़ें सड़ गईं। कई स्थानों पर मिट्टी का कटाव इतना गंभीर था कि उपजाऊ परत बह गई। धान, सोयाबीन, कपास और सब्जियों जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ। जिन किसानों ने कर्ज लेकर बीज और उर्वरक खरीदे थे, उनके सामने दोहरी मार पड़ी—एक ओर फसल नष्ट हुई और दूसरी ओर कर्ज चुकाने की चिंता बढ़ गई।

राज्य सरकार ने कृषि मद में लगभग 19,781.39 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है। इसमें 0 से 2 हेक्टेयर तक फसल क्षति के लिए 8,812.10 करोड़ रुपये तथा 2 से 3

हेक्टेयर तक की क्षति के लिए 848.17 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। कृषि भूमि के नुकसान के लिए 193.09 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जबकि बीज और उर्वरक के नुकसान की भरपाई हेतु 9,611.17 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। पशुधन की मृत्यु और क्षति के लिए 26.20 करोड़ रुपये तथा मत्स्य क्षेत्र के लिए 87.83 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत घरों के नुकसान के लिए 39.66 करोड़ रुपये और जिला स्तर पर पहले से वितरित सहायता की प्रतिपूर्ति के लिए 163.17 करोड़ रुपये शामिल हैं।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की यह मांग इस बात को दर्शाती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितनी गहरी चोट पहुंची है। महाराष्ट्र जैसे बड़े कृषि प्रधान राज्य में जब फसलें नष्ट होती हैं, तो इसका असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे जुड़े मजदूरों, व्यापारियों और स्थानीय बाजारों पर भी पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह कम हो जाता है और स्थानीय रोजगार के अवसर घटते हैं।

आपदा का प्रभाव केवल खेतों तक सीमित नहीं रहा। भारी बारिश और बाढ़ ने सड़कों, पुलों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक भवनों को भी व्यापक नुकसान पहुंचाया। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए लगभग 10,000.27 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 4,066.98 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 4,585.70 करोड़ रुपये की मांग की गई है, ताकि गांवों की आंतरिक सड़कों और सामुदायिक ढांचे को पुनर्स्थापित किया जा सके।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के लिए 80.86 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग के लिए 260.96 करोड़ रुपये और स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 146.50 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसके अलावा सामुदायिक भवनों के पुनर्निर्माण के लिए 502.64 करोड़ रुपये तथा सिंचाई विभाग के लिए 350.34 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 6.29 करोड़ रुपये की मांग भी शामिल है। यह स्पष्ट है कि बाढ़ ने राज्य के विकास ढांचे को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।

राज्य सरकार का कहना है कि उसने केंद्र से सहायता की मांग करने के साथ ही मामले की निरंतर निगरानी शुरू कर दी है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जैसे ही केंद्रीय सहायता स्वीकृत हो, पुनर्निर्माण और राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि, निर्णय में देरी के कारण कई परियोजनाएं लंबित हैं और प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी व्यवस्थाओं के सहारे काम चलाया जा रहा है।

राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव ने स्पष्ट किया है कि केंद्र की सहायता का इंतजार किए बिना ही राज्य सरकार ने प्राथमिक स्तर पर प्रभावित नागरिकों को मदद पहुंचाई है। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से तात्कालिक राहत प्रदान की, जिसमें खाद्यान्न वितरण, अस्थायी आवास, पशुधन सहायता और फसल क्षति के लिए अंतरिम मुआवजा शामिल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार प्रभावितों को अकेला नहीं छोड़ेगी और पुनर्वास कार्य जारी रखेगी।

फिर भी, व्यापक पुनर्निर्माण और स्थायी समाधान के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है, जो केवल राज्य के संसाधनों से संभव नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि केंद्र से मांगी गई सहायता शीघ्र स्वीकृत होती है, तो न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। समय पर सहायता मिलने से किसान अगली बुवाई के लिए तैयार हो सकेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां फिर से गति पकड़ सकेंगी।

आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी यह घटना एक महत्वपूर्ण सबक है। बदलते जलवायु पैटर्न और अत्यधिक वर्षा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। बेहतर जल निकासी व्यवस्था, मजबूत तटबंध, उन्नत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना समय की मांग है। यदि इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, तो भविष्य में इस तरह की आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

फिलहाल, राज्य के किसान और ग्रामीण परिवार केंद्रीय सहायता के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके लिए यह केवल आर्थिक सहायता का सवाल नहीं है, बल्कि अपने जीवन और आजीविका को फिर से पटरी पर लाने की उम्मीद है। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, राहत की यह प्रतीक्षा और भी गहरी होती जा रही है। अब नजरें केंद्र सरकार के निर्णय पर टिकी हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द स्थायी राहत मिल सके और महाराष्ट्र के गांव फिर से समृद्धि की ओर कदम बढ़ा सकें।

प्रतिबंधित जैमर और एंटी-ड्रोन उपकरणों की बिक्री पर सख्त शिकंजा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की सुरक्षा और दूरसंचार व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील उपकरणों की खुलेआम बिक्री पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने छह प्रमुख ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है कि उनके माध्यम से 'एंटी-ड्रोन सिस्टम', 'ड्रोन जैमर' और 'जीपीएस जैमर' जैसे प्रतिबंधित उपकरणों की बिक्री किस आधार पर की जा रही थी। यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है, जब देश में डिजिटल मार्केटप्लेस का तेजी से विस्तार हो रहा है और सुरक्षा से जुड़े उपकरणों तक आम लोगों की पहुंच बढ़ती जा रही है।

सीसीपीए के अनुसार, IndiaMART, AirOne Robotics, Maverick Drones, एवरसे, एक्सबूम और जावियट एयरोस्पेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन उपकरणों को खुलेआम सूचीबद्ध किया गया था और संभावित खरीदारों को इन्हें खरीदने का विकल्प दिया जा रहा था। इन उत्पादों का अनियंत्रित रूप से उपलब्ध होना गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये उपकरण वायरलेस सिग्नल को बाधित करने में सक्षम होते हैं और इनका उपयोग केवल अधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा ही किया जा सकता है।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के उपकरणों की बिक्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के साथ-साथ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ये कानून स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति या निजी संस्था को बिना लाइसेंस के ऐसे उपकरणों का आयात,

बिक्री या उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इन उपकरणों के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क, जीपीएस सिस्टम और अन्य वायरलेस संचार को बाधित किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, ड्रोन और जीपीएस जैमर जैसे उपकरणों का उपयोग सैन्य और सुरक्षा अभियानों में अत्यंत नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इनका उद्देश्य संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों को रोकना, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करना और आतंकवादी गतिविधियों को विफल करना होता है। यदि ये उपकरण गलत हाथों में पहुंच जाएं, तो उनका उपयोग आपराधिक गतिविधियों, जासूसी या महत्वपूर्ण सेवाओं को बाधित करने के लिए किया जा सकता है। यही कारण है कि सरकार ने इनकी बिक्री और उपयोग पर सख्त नियंत्रण लागू किया है। भारत में ऐसे उपकरणों के आयात और उपयोग के लिए दूरसंचार विभाग और वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन (डब्ल्यूपीसी) से विशेष लाइसेंस लेना अनिवार्य है। विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत केवल अधिकृत सरकारी एजेंसियों, सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन इकाइयों को ही इन उपकरणों की खरीद और उपयोग की अनुमति दी जाती है। किसी भी निजी संस्था या व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के इन उपकरणों की बिक्री या खरीद कानून का उल्लंघन मानी जाती है।

सीसीपीए ने संबंधित कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे पिछले दो वर्षों के दौरान इन उपकरणों की बिक्री से संबंधित सभी विवरण प्रस्तुत करें। इसमें खरीदारों की पहचान, बिक्री की तिथि, आयात लाइसेंस की प्रतियां और बिक्री के लिए अपनाए गए कानूनी आधार की जानकारी शामिल है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कहीं इन उपकरणों का उपयोग अवैध गतिविधियों में तो नहीं किया गया है।

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किए जाने वाले उत्पादों की वैधता की जांच करें। डिजिटल मार्केटप्लेस केवल एक माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के बीच भरोसे का सेतु भी हैं। यदि इन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित या अवैध वस्तुओं की बिक्री होती है, तो इससे न केवल कानून का उल्लंघन होता है, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।

सरकार की यह कार्रवाई डिजिटल अर्थव्यवस्था में बढ़ती पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में ई-कॉमर्स का दायरा तेजी से बढ़ा है और लाखों विक्रेता अपने उत्पाद ऑनलाइन बेच रहे हैं। इस तेजी के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक हो गया है कि कोई भी प्रतिबंधित या खतरनाक उत्पाद बिना उचित अनुमति के बाजार में उपलब्ध न हो।

राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जैमर और एंटी-ड्रोन उपकरणों की अनियंत्रित उपलब्धता से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे हवाई अड्डों, सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, ये उपकरण आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन विभाग के संचार नेटवर्क को भी बाधित कर सकते हैं, जिससे आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया समय बढ़ सकता है और जान-माल का नुकसान हो सकता है।

सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में और भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर सूचीबद्ध उत्पादों की नियमित जांच करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी प्रतिबंधित उपकरण बिना अनुमति के उपलब्ध न हो। यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं।

इस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी है। कई बार लोग तकनीकी जानकारी के अभाव में ऐसे उपकरण खरीद लेते हैं, बिना यह जाने कि उनका उपयोग अवैध है। सरकार चाहती है कि नागरिक कानूनों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध या प्रतिबंधित उपकरण की खरीद से बचें।

आढ़तीया कपड़ा एसोसिएशन का भव्य होली स्नेह मिलन आयोजन

(जीएनएस)। सूरत। रंगों, उल्लास और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक होली का पावन पर्व नजदीक आते ही पूरे शहर में उत्साह और तैयारियों का माहौल बन गया है। इसी कड़ी में आढ़तीया कपड़ा एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली स्नेह मिलन एवं फागुन महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष आयोजन शनिवार, 28 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक 205, राजहंस इम्पीरिया, सोमोलाई मंदिर के सामने, मानदरवाजा स्थित परिसर में आयोजित होगा। इस आयोजन का उद्देश्य केवल होली का उत्सव मनाना ही नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, सौहार्द और एकता के भाव को मजबूत करना भी है। सूरत, जिसे देश की टेक्सटाइल राजधानी के रूप में जाना जाता है, यहां के व्यापारी वर्ग की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हमेशा से ही विशेष महत्व रखती हैं। व्यापारिक व्यस्तताओं के बीच इस तरह के आयोजन लोगों को एक मंच प्रदान करते हैं, जहां वे अपने पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हुए एक-दूसरे के साथ खुशियां बांट सकें। आढ़तीया कपड़ा एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम भी इसी भावना का प्रतीक है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। होली स्नेह मिलन एवं फागुन महोत्सव का मुख्य आकर्षण फूलों की होली होगी। फूलों से होली खेलने की यह परंपरा विशेष रूप से शांति, पवित्रता और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इसमें रंगों के बजाय सुगंधित फूलों का उपयोग किया जाता है, जिससे

वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी लोग बिना किसी संकोच या असुविधा के उत्सव का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार का आयोजन पारंपरिक होली के साथ-साथ आधुनिक संवेदनशीलता और स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी विशेष महत्व रहेगा। जयपुर से आने वाले प्रख्यात गायक अपनी मधुर आवाज और पारंपरिक फागुन गीतों के माध्यम से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। होली के पारंपरिक गीत, फाग और लोकधुनें कार्यक्रम के वातावरण को और अधिक जीवंत और आनंदमय बना देंगी। संगीत और रंगों का यह संगम सभी उपस्थित लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगा। एसोसिएशन के प्रमुख प्रहलाद अग्रवाल ने इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि समाज के लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। उन्होंने कहा कि होली का पर्व हमें आपसी मतभेद भुलाकर एक-दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द के साथ जुड़ने का संदेश देता है। इस प्रकार के आयोजन से समाज में सकारात्मकता और एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम में आने वाले सभी अतिथियों के लिए ठंडाई और विशेष स्वादिष्ट अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। ठंडाई होली के पर्व का एक पारंपरिक पेय है, जो उत्सव की पहचान माना जाता है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और नाश्ते भी उपलब्ध रहेंगे, जिससे उपस्थित लोग उत्सव का पूरा आनंद ले सकें।

यह आयोजन न केवल मनोरंजन और उत्सव का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा देगा। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोग, उनके परिवार और समाज के अन्य सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल होकर एक-दूसरे के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर सकेंगे। इस प्रकार के आयोजन समाज में सामाजिक समरसता और सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहित करते हैं।

सूरत का कपड़ा उद्योग देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहां के व्यापारी न केवल आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आढ़तीया कपड़ा एसोसिएशन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि व्यापारिक संगठन केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इस आयोजन के माध्यम से नई पीढ़ी को भी अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आज के आधुनिक और व्यस्त जीवन में इस प्रकार के आयोजन लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने और पारंपरिक त्योहारों के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। इससे समाज में सांस्कृतिक निरंतरता बनी रहती है और आने वाली पीढ़ियां भी इन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होती हैं।

एसोसिएशन ने सभी समाजजनों और व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में शामिल हों और इस होली को यादगार बनाएं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सभी के लिए खुला है और इसका उद्देश्य केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश फैलाना है।

इस प्रकार, आढ़तीया कपड़ा एसोसिएशन द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन एवं फागुन महोत्सव न केवल एक सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि यह समाज को जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। यह आयोजन निश्चित रूप से सूरत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में एक यादगार और प्रेरणादायक अध्याय जोड़ने वाला साबित होगा।

नगर निगम में रिश्वत कांड से प्रशासनिक तंत्र में मचा भूचाल

(जीएनएस)। सूरत। देश के प्रमुख औद्योगिक शहर और तेजी से विकसित हो रहे शहरी केंद्र सूरत में नगर प्रशासन की साख को झटका देने वाला एक गंभीर भ्रष्टाचार मामला सामने आया है। शहर के सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसएमसी) के लिंबायत ज़ोन में कार्यरत एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एक स्थानीय पत्रकार के खिलाफ कथित रूप से 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले का खुलासा होने के बाद पूरे नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह कार्रवाई एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा की गई है, जिसने शिकायत के आधार पर जांच करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला केवल रिश्वत मांगने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासनिक पद के दुरुपयोग, आपराधिक कदाचार और एक पत्रकार की कथित मिलीभगत जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं, जिसने इस पूरे प्रकरण को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता एक निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके निर्माण स्थल को लेकर नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ का नोटिस जारी किया गया था। यह नोटिस नगर निगम की नियमित कार्रवाई का हिस्सा था, लेकिन आरोप है कि इस नोटिस को कार्रवाई में बदलने या रोकने के नाम पर अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लिंबायत ज़ोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विपुल शशिकांत गणेशवाला और एक स्थानीय अखबार से जुड़े पत्रकार मोहम्मद इस्माइल उर्फ परवाना पठान ने मिलकर उससे पहले 21 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, बातचीत के दौरान दोनों आरोपियों ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि यदि रिश्वत की रकम दी जाती है, तो नगर

निगम की कार्रवाई को रोका जा सकता है और निर्माण कार्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह भी आरोप है कि रिश्वत की रकम पर कई दौर की बातचीत के बाद इसे घटाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया, जो कथित रूप से अंतिम रूप से तय की गई राशि थी। इस रकम को किस्तों में देने की योजना बनाई गई थी, जिसमें पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपये नकद देने की बात तय हुई थी। हालांकि, शिकायतकर्ता इस अवैध मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। उसने इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई और कानून का सहारा लेने का निर्णय लिया। उसने सीधे एसीबी से संपर्क किया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच शुरू की और आरोपों की पुष्टि के लिए एक जाल बिछाने की योजना बनाई। 19 फरवरी को एसीबी की टीम ने तय योजना के अनुसार कार्रवाई की। शिकायतकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह आरोपियों द्वारा मांगी गई पहली किस्त की राशि देने के लिए तैयार रहे। योजना के अनुसार पत्रकार मोहम्मद इस्माइल शिकायतकर्ता से 4 लाख रुपये की नकद राशि लेने के लिए मौके पर पहुंचा। शिकायतकर्ता ने तय स्थान पर जाकर राशि सौंप दी, लेकिन जैसे ही एसीबी की टीम मौके पर पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही आरोपी पत्रकार वहां से फरार हो गया।

इस घटनाक्रम ने जांच को और अधिक जटिल बना दिया, क्योंकि आरोपी नकदी लेकर मौके से भागने में सफल रहा। वहीं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विपुल गणेशवाला भी उस समय मौके पर मौजूद नहीं मिले। इससे यह संदेह और मजबूत हो गया कि दोनों आरोपियों को पहले से ही कार्रवाई की भनक लग चुकी थी या उन्होंने किसी तरह स्थिति को भांप लिया था।

एसीबी अधिकारियों ने तत्काल इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह आरोप लगाया गया है कि दोनों ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए शिकायतकर्ता से अवैध रूप से धन की मांग की और आपराधिक कदाचार किया। यह मामला न केवल भ्रष्टाचार का है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त संभावित अनियमितताओं की ओर भी संकेत करता है। इस घटना के सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन में व्यापक स्तर पर हलचल मच गई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक समीक्षा शुरू कर दी है। नगर निगम के कई अधिकारियों और कर्मचारियों में इस घटना को लेकर चिंता और असहजता का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि यह मामला सीधे प्रशासनिक विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। इस मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें एक पत्रकार का नाम भी सामने आया है। आमतौर पर पत्रकार समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस मामले में एक पत्रकार पर ही भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगना बेहद गंभीर माना जा रहा है। इससे पत्रकारिता की नैतिकता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। एसीबी की टीमें फिलहाल दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और आरोपियों के संपर्कों की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसी इस बात का भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं या यह एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आरोप साबित होते हैं, तो दोनों आरोपियों को गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर कठोर सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान है। इसके अलावा, प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सेवा से निलंबन या बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। यह घटना एक बार फिर यह दर्शाती है कि भ्रष्टाचार की समस्या अभी भी प्रशासनिक तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि सरकार और जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि अभी भी सुधार की आवश्यकता है। इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा साहस दिखाते हुए एसीबी से संपर्क करना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना एक सकारात्मक उदाहरण माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने नगर निगम प्रशासन को अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रशासन सख्त कदम उठाता है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करता है, तो इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, बल्कि जनता का प्रशासन पर विश्वास भी मजबूत होगा। फिलहाल, पूरे शहर की नजरें इस मामले की जांच पर टिकी हुई हैं। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि जांच में आगे क्या खुलासा होता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता की एक महत्वपूर्ण याद दिलाता है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

कोर्ट ने कहा-राज्यों के दूरगामी हित देखें

यह भारतीय लोकतंत्र की विडंबना ही कही जाएगी कि राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनाव जीतने का जरिया ही बना लिया है। मतदाताओं को चंद आर्थिक लाभ व सुविधाएं देकर मुफ्त की रेवड़ियों को सफलता का शॉर्टकट माना जाने लगा है। यही वजह है कि कुछ राज्यों में आसन्न चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाओं की संस्कृति के वर्चस्व को देखते हुए देश की शीर्ष अदालत ने तल्ख टिप्पणी की है। जिससे यह मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श में शामिल हो गया है। उल्लेखनीय है कि अगले दो-तीन महीनों में देश के चार प्रमुख राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि, लोकतंत्र की कल्याणकारी अवधारणा के चलते लोकहित में चलायी जाने वाली जनहितकारी योजनाएं शासन का अनिवार्य स्तंभ भी रही हैं। लेकिन लक्षित समर्थन और चुनाव पूर्व दिखायी जाने वाली अतिरेक उदारता के बीच अंतर तेजी से धुंधला होता जा रहा है। देश की शीर्ष अदालत ने इस बाबत चेतावनी दी है कि मुफ्त की योजनाओं का अनियंत्रित विस्तार राज्यों के राजकोषीय अनुशासन को कमजोर कर सकता है। निस्संदेह, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राज्यों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की खास तौर से देखभाल करें। हालांकि, जब राजस्व घाटे वाले राज्य मुफ्त की योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। विडंबना यह है कि जिस धनराशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम बनाने और शिक्षा की सुविधा को समृद्ध करने के लिये किया जाना चाहिए, वो राशि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये खर्च कर दी जाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि राजनेता मुफ्त की बिजली, मुफ्त बस यात्रा और नकद राशि बांटने की होड़ में शामिल हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लोकलुभावनवाद के आगे राजकोषीय विवेक कमजोर पड़ रहा है।

निस्संदेह, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बाबत तार्किक प्रश्न पूछा है कि राज्य मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिये बजट प्रस्ताव क्यों नहीं पेश करते? इसमें दो राय नहीं कि रोजगार के नये अवसर पैदा करना जन साधारण के सशक्तीकरण का एक स्थायी रूप है। जो लोगों को स्वावलंबी बनाता है। वहीं दूसरी ओर वोटरों को लुभाने के लिये सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा लगातार जारी की जा रही मुफ्त की योजनाएं लोगों को अकर्मण्य बना देती हैं। लोग परिश्रम से आर्थिक उपलब्धि हासिल करने के बजाय सरकारी सुविधा पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें। निस्संदेह,चुनावी निष्पक्षता के लिये यह आवश्यक हो गया है कि चुनाव से पहले घोषित की गई या लागू की गई लोकलुभावनी नीतियों व योजनाओं की गहन पड़ताल की जाए। विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पिछले साल अक्तूबर में आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 15,600 करोड़ रुपये दिए गए थे। जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कदम था। निर्विवाद रूप से सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की सुनियोजित कोशिश विपक्षी दलों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से वंचित करती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपरोक्ष रूप से रिश्वत देने के प्रयासों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही इस दिशा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब चाहे कोई बड़ा राजनीतिक दल इसमें शामिल क्यों न हो। निर्विवाद रूप से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। वहीं दूसरी ओर स्वस्थ लोकतंत्र के लिये जरूरी है कि देश का मतदाता परिपक्व व जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करके लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करे।

खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी मौसम अनुकूल खेती

"जलवायु बदलाव के चलते फरवरी में तापमान सामान्य से ज्यादा हो रहा है। इसका प्रभाव गेहूं आदि रबी फसलों व आम की पैदावार पर है। यानी खाद्य सुरक्षा संकट में है। इसका समाधान 'क्लाइमेट स्मार्ट कृषि' में निहित है। यानी इसमें मल्चिंग, माइक्रो सिंचाई व 'हीट टॉलरेंट' किस्में मददगार होंगी।

फरवरी का महीना आमतौर पर गुलाबी ठंड और वसंत की मंद बयार का प्रतीक माना जाता रहा है। यह वह समय होता है जब रबी की फसलें और आम के बगीचे अपने यौवन पर होते हैं। लेकिन साल 2026 की यह फरवरी डराने वाली है। फरवरी के मध्य में ही देश के एक बड़े हिस्से में पारा 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है, जो सामान्य से करीब 5 से 7 डिग्री अधिक है। यह केवल एक मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि 'ग्लोबल वार्मिंग' का वह क्रूर चेहरा है जो सीधे हमारी थाली और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रहार कर रहा है।

जलवायु परिवर्तन का सबसे घातक प्रहार हमारी खाद्य सुरक्षा और 'फलों के राजा' आम पर हो रहा है। रबी की मुख्य फसल गेहूं के लिए फरवरी का दूसरा पखवाड़ा 'ग्रैन फिलिंग' यानी बालियों में दाना भरने की अवस्था का होता है। इस नाजुक दौर में अचानक बढ़ी गर्मी 'थर्मल स्ट्रेस' पैदा कर रही है। जब तापमान 30 डिग्री के ऊपर बना रहता है, तो पौधों के भीतर चयापचय की प्रक्रिया असामान्य रूप से तेज हो जाती है और दाना पूरी तरह विकसित होने से पहले ही सख्त होने लगता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में 'फोर्स्ड मेच्योरिटी' कहा जाता है। परिणामस्वरूप, दाना छोटा, हल्का और झुर्रियों वाला रह जाता है। कृषि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि तापमान में इसी तरह की वृद्धि जारी रही, तो गेहूं की पैदावार में प्रति हेक्टेयर 15 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। सागर और औरैया के खेतों से आ रही रिपोर्टें बताती हैं कि गेहूं की बालियां समय से पहले सफेद पड़ रही हैं, जो सीधे तौर पर किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि आम का पुष्पन जाड़े के अंत और वसंत की शुरुआत में स्थिर तापमान और मध्यम आर्द्रता में होता रहा है। किंतु तापमान की वर्तमान अनिश्चितता ने इस प्रक्रिया को 'रोलर-कोस्टर' बना दिया है। इसके विपरीत, यदि अचानक तापमान गिरता है, तो फूलों का खुलना असमान हो जाता है। सुबह की अत्यधिक नमी फफूंदजनित रोगों का जोखिम बढ़ा रही है, जबकि दोपहर की शुष्क हवा पराग के अंकुरण को बाधित कर रही है। नतीजा यह है कि या तो फूल गिर रहे हैं, या निषेचन के बाद भी फल टिक नहीं पा रहे हैं। आमतौर पर सर्दियों में होने वाली 'मावट' या बारिश फसलों के लिए अमृत समान होती थी, लेकिन इस साल शुष्कता और बढ़ती गर्मी ने मिट्टी की नमी को सोख लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले एक दशक में फरवरी के महीने में लू जैसी स्थितियों की आवृत्ति बढ़ी है। इस पैटर्न में भारत के मौसम चक्र से 'वसंत' ऋतु धीरे-धीरे गायब हो रही है। इसका असर केवल गेहूं और आम पर ही नहीं, बल्कि सरसों और दलहन पर भी पड़ रहा है। सरसों की फलियों में तेल की मात्रा कम होने की आशंका है और चने के पौधों में फूल समय से पहले ही झड़ रहे हैं।

इस विकट परिस्थिति का निदान अब केवल पारंपरिक खेती के ढर्रे पर चलकर संभव नहीं है। हमें 'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर' यानी जलवायु-अनुकूल कृषि की ओर युद्धस्तर पर बढ़ना होगा। मिट्टी की नमी बचाने के लिए गन्ने की सूखी पत्तियों, भूसे या सूखी घास से 'मल्चिंग' करना अब अनिवार्यता है। यह तकनीक सतह के तापमान को स्थिर रखती है और पानी के वाष्पीकरण को रोकती है। इसके साथ ही, सूक्ष्म-सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) को अपनाकर 'कम पानी—ज़्यादा असर' के सिद्धांत पर काम करना होगा। बागों की मेढ़ों पर कटहल, बांस या नीम जैसे वायुरोधी अवरोध लगाने चाहिए ताकि तेज पछिया हवाओं से फूलों और फलों का बचाव हो सके।

वैज्ञानिकों के अनुसार, पुष्पन के दौरान बोरॉन और जिंक जैसे सूक्ष्म-पोषक तत्वों का संतुलित छिड़काव फूलों की जीवन-क्षमता को बढ़ा सकता है। साथ ही, कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए मौसम-पूर्वानुमान आधारित छिड़काव ही कारगर होगा।

ब्लॉक-स्तरीय मौसम परामर्श और सटीक पूर्वानुमान आज किसानों के लिए सबसे बड़े 'निर्णय-सहायक उपकरण' हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किस्मों का विवेकपूर्ण चयन भी महत्वपूर्ण है। आम्रपाली, मल्लिका और गेहूं की 'हीट टॉलरेंट' किस्में जैसे डीबीडब्ल्यू 187 बदलती परिस्थितियों में बेहतर अनुकूलन दिखा रही हैं।

यदि देश के कुल अनाज उत्पादन में बड़ी गिरावट आती है, तो इसका असर केवल किसान की आय पर ही नहीं, बल्कि देश की जीडीपी और आम आदमी की रसोई पर पड़ेगा। समझना होगा कि धरती का बढ़ता तापमान हमारे विकास के मॉडल पर प्रकृति का प्रतिघात है। मिट्टी की नमी को बचाना और बदलती जलवायु के अनुसार खुद को ढालना अब हमारी पसंद नहीं, बल्कि अस्तित्व की मजबूरी है।

नीति-निर्माताओं, कृषि वैज्ञानिकों और स्वयं किसानों को एक मंच पर आकर इस चुनौती का सामना करना होगा। विज्ञान-आधारित प्रबंधन और समयबद्ध निर्णयों के साथ हम इस नई सच्चाई के साथ तालमेल बिठा सकते हैं।

प्रेरणा

अपने स्वभाव की राह ही सच्ची महानता का मार्ग

एक शांत आश्रम के प्रांगण में सुबह की पहली किरणें धीरे-धीरे धरती को स्पर्श कर रही थीं। पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को जीवंत बना रहा था, लेकिन उसी आश्रम के एक कोने में बैठा एक शिष्य अपने भीतर भारी बोझ महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, उसकी आंखों में प्रश्न थे, और उसके मन में असंतोष की एक गहरी लहर उठ रही थी। वह कई दिनों से स्वयं को दूसरों से तुलना कर रहा था और हर बार उसे यही लगता था कि वह पीछे रह गया है।

आखिर एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। शिष्य ने उनके चरणों में बैठते हुए कहा, "गुरुदेव, मेरा मन बहुत व्याकुल है। मैं जहां भी देखता हूं, मुझे कोई न कोई मुझसे बेहतर दिखाई देता है। कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान है, कोई मुझसे अधिक तेज़ है, कोई मुझसे अधिक सफल है। मुझे लगता है कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं हमेशा पीछे ही रह जाऊंगा।"

गुरु ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलीं और शिष्य की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी शांति भी थी। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वे उठे और शिष्य को अपने साथ चलने का संकेत किया। दोनों आश्रम से निकलकर पास के जंगल की ओर बढ़ने लगे। जंगल में प्रवेश करते ही प्रकृति की विशालता सामने थी। ऊंचे-ऊंचे पेड़ आकाश को छूते हुए प्रतीत हो रहे थे। कहीं छोटे पौधे थे, कहीं विशाल वृक्ष। गुरु एक स्थान पर रुके, जहां एक लंबा, सीधा साल का पेड़ खड़ा था और उसके पास एक छोटा सा आम का पौधा था, जिसमें छोटे-छोटे हरे फल लगे हुए थे।

गुरु ने शिष्य से पूछा, "तुम्हें क्या दिखाई देता है?"

शिष्य ने साल के पेड़ की ओर देखते हुए कहा, "गुरुदेव, यह साल का पेड़ कितना महान है। यह कितना ऊंचा और शक्तिशाली है। और इसके पास यह छोटा सा आम का पौधा कितना छोटा और कमजोर लगता है।"

गुरु मुस्कुराए और बोले, "तुम्हें पता है, यह साल का पेड़ सौ वर्षों में इतना बड़ा हुआ है। इसने समय लिया, धैर्य रखा, और धीरे-धीरे आकाश की ओर बढ़ता गया। और यह आम का पौधा, यह केवल पांच वर्षों का है, लेकिन यह पहले ही फल देने लगा है। यह लोगों को मिठास दे रहा है, पक्षियों को भोजन दे रहा है।"

शिष्य चुपचाप सुन रहा था।

गुरु ने आगे कहा, "अब सोचो, यदि यह आम का पौधा साल के पेड़ जैसा बनने की कोशिश करे, तो क्या होगा?"

शिष्य ने कुछ क्षण सोचकर कहा, "शायद यह कभी फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि यह अपनी ऊर्जा केवल ऊंचा होने में लगा देगा।"

गुरु ने सिर हिलाया और कहा, "और यदि साल का पेड़ आम बनने की कोशिश करे, तो क्या होगा?"

शिष्य ने उत्तर दिया, "तब वह अपनी विशालता खो देगा, अपनी छाया खो देगा, और शायद कभी उतना मजबूत नहीं बन पाएगा।"

गुरु ने गहरी आवाज़ में कहा, "यही जीवन का सत्य है। हर एक का स्वभाव अलग है। हर एक की गति अलग है। हर एक का उद्देश्य अलग है। तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। जब तुम किसी और बनने की कोशिश करते हो, तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर चले जाते हो।"

शिष्य के भीतर कुछ हलचल हुई। उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो।

गुरु ने आगे कहा, "प्रकृति में कोई भी वृक्ष दूसरे से तुलना नहीं करता। गुलाब कभी कमल बनने की कोशिश नहीं करता। सूर्य कभी चंद्रमा बनने की इच्छा नहीं करता। हर एक अपने स्वभाव में पूर्ण है। और इसी कारण यह संसार संतुलित और सुंदर है।"

शिष्य ने पूछा, "लेकिन गुरुदेव, हम कैसे जानें कि हमारा स्वभाव क्या है?"

गुरु ने उत्तर दिया, "जब तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनते हो, जब तुम बिना तुलना के अपने कार्य में आनंद अनुभव करते हो, तब तुम अपने स्वभाव के मार्ग पर होते हो। स्वभाव वह है, जिसमें तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ता, जिसमें तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, जिसमें तुम सहज हो जाते हो।"

शिष्य की आंखों में अब समझ की एक नई चमक थी।

गुरु ने आगे कहा, "तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं है। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा केवल अपने कल से है। यदि तुम आज अपने कल से बेहतर हो, तो तुम सही दिशा में हो। महानता दूसरों से आगे निकलने में नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर छिपी क्षमता को पहचानने में है।"

यह सुनकर शिष्य के मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक एक ऐसी दौड़ में भाग रहा था, जिसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं था। वह दूसरों की गति देखकर स्वयं को कम आंक रहा था, जबकि उसकी अपनी गति, उसका अपना मार्ग, उतना ही महत्वपूर्ण था। उस दिन जंगल से लौटते समय शिष्य का मन पहले जैसा नहीं था। अब वह हल्का था, शांत था। उसने आकाश की ओर देखा। सूर्य धीरे-धीरे ऊपर उठ रहा था, अपने स्वभाव के अनुसार, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी तुलना के।

शिष्य ने उसी क्षण एक संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह अब किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करेगा। वह अपने स्वभाव को पहचानेगा, अपनी गति से आगे बढ़ेगा, और अपने भीतर की क्षमता को विकसित करेगा।

समय बीतता गया। शिष्य ने अपने कार्यों में तुलना को छोड़ दिया। उसने केवल अपने विकास पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे-धीरे उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उसका मन शांत रहने लगा। अब वह दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करता था, बल्कि प्रेरणा लेता था।

एक दिन गुरु ने उसे फिर बुलाया और पूछा, "अब तुम्हें कैसा लगता है?"

शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, "गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि मेरी राह मेरी अपनी है। मुझे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। मुझे केवल चलते रहना है, अपने स्वभाव के अनुसार।"

गुरु ने संतोष से उसकी ओर देखा और कहा, "यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब तुम अपने स्वभाव को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तब तुम्हारा हर कदम पूर्ण होता है।"

उस दिन से शिष्य ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लिया था। उसने समझ लिया था कि महानता किसी और बनने में नहीं है, बल्कि स्वयं बनने में है।

और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है—जब तुम अपने स्वभाव की राह पर चलते हो, तब तुम्हें न कोई रोक सकता है, न कोई पीछे छोड़ सकता है। क्योंकि उस मार्ग पर केवल तुम हो, तुम्हारा सत्य है, और तुम्हारी सच्ची महानता है।

असमानताओं पर प्रहार, समानता का विस्तार: एक सार्थक पुकार

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम "समावेश को सशक्त बनानाः सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना" हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं-चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है। आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील, पुरुष और महिला, सक्षम और दिव्यांग-इन सबके बीच संसाधनों की असमान पहुंच सामाजिक तनाव को जन्म देती है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय का अर्थ है इन अंतरों को पहचानना और उन्हें पाटने के लिए लक्षित, संवेदनशील और पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना। सम्मानजनक कार्य की अवधारणा भी सामाजिक न्याय के केंद्र में है। केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा कार्य-संस्कृति बनाना आवश्यक है जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मानव गरिमा के साथ जुड़ा हो। यदि विकास केवल आंकड़ों में सीमित रह जाए और आम नागरिक के जीवन में राहत न ला सके, तो वह विकास नहीं, केवल विस्तार है। मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र इस युग की अनिवार्यता बन चुका है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक-इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है।

समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा-पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। "संतुष्टिकरण" बनाम "तुष्टिकरण" की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है।

आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धनतंत्र एवं सत्तातंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय-व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, फ्रांसिस बेकन ने ठीक कहा था कि 'यह ऐसी न्याय-व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की यंत्रणा के लिये दस अपराधी दोषमुक्त और रिहा हो सकते हैं।' रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि 'मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है।' लेकिन हमारे देश के कानून एवं शासन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता, आम आदमी सजा का जीवन जीने को विवश है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक एकता भंग नहीं की जा सकती। शासन और प्रशासन की प्रत्येक नीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। यदि शक्ति के स्रोत जनहित में प्रयुक्त न हों, तो वे असंतोष और अविश्वास को जन्म देते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है।

अभियान

दक्षिणमुखी महाकाल की कृपा से मिटता मृत्यु भय और संवरता जीवन

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ तीर्थ ऐसे हैं जिनका प्रभाव केवल मन पर नहीं, बल्कि भाग्य और चेतना पर भी पड़ता है। उन्हीं दिव्य स्थलों में एक है महाकालेश्वर मंदिर, जो पवित्र नगरी उज्जैन में स्थित है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि काल और महाकाल के रहस्य का जीवंत केंद्र माना जाता है। यहां पहुंचकर व्यक्ति केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि समय, मृत्यु और आत्मा के शाश्वत सत्य से साक्षात्कार करता है। महाकाल का अर्थ है वह शक्ति जो स्वयं काल के भी पार है। जब भक्त इस भाव से यहां आता है, तो उसके भीतर से भय, असुरक्षा और अस्थिरता धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है।

महाकालेश्वर बारह ज्योतिर्लिंगों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं क्योंकि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं। किंतु महाकाल का दक्षिण की ओर मुख होना यह दर्शाता है कि वे मृत्यु के भी स्वामी हैं। यह प्रतीक बताता है कि जो उनकी शरण में आता है, वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति केवल शारीरिक सुरक्षा का आश्वासन नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक निर्भयता का अनुभव है। जब व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं रहता, तब वह जीवन को अधिक स्पष्टता और साहस के साथ जी पाता है।

महाकालेश्वर शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात यह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र में दूषण नामक एक असुर ने अत्याचार फैलाया था। साधु-संतों और भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और उस असुर का अंत किया। उसी स्थान पर वे महाकाल रूप में विराजमान हो गए। यह कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि जब अधर्म और भय अपने चरम पर पहुंचते हैं, तब दिव्य शक्ति स्वयं हस्तक्षेप करती है। महाकाल का स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि अन्याय और अंधकार स्थायी नहीं होते। महाकाल मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंदपुराण के अवंती खंड में महाकाल की महिमा का विस्तृत वर्णन है। शिवपुराण में भी इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महिमा का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अपनी अमर कृति मेघदूतम में उज्जैन और महाकाल का उल्लेख किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह स्थान केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

उज्जैन को पृथ्वी की नाभि कहा जाता है। प्राचीन काल में यह खगोल और गणित का प्रमुख केंद्र था। समय की गणना और ज्योतिषीय शोध के लिए यह स्थान विशेष महत्व रखता था। कर्क रेखा के इस क्षेत्र से गुजरने की मान्यता इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। यही कारण है कि यहां साधना और ध्यान करने वाले साधकों को गहन आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। महाकाल का संबंध केवल आस्था से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय समय चक्र से भी जोड़ा जाता है।

महाकाल मंदिर की सबसे अद्वितीय परंपरा भस्म आरती है। प्रातःकाल होने वाली इस आरती में भगवान का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। भस्म इस सत्य का प्रतीक है कि शरीर और भौतिक संसार नश्वर हैं। अंततः सब कुछ भस्म हो जाना है। यह आरती भक्त को जीवन की अस्थिरता का बोध कराती है और उसे यह समझने में सहायता करती है कि केवल आत्मा शाश्वत है। जब यह बोध भीतर उतरता है, तब व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। वह क्षणभंगुर वस्तुओं के पीछे भागना छोड़कर स्थायी मूल्यों की ओर अग्रसर होता है।

महाकाल के दर्शन से व्यक्ति के जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ होता है। पहले जो भय उसे घेरता था, वह धीरे-धीरे कम होने लगता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा कम होने लगता है। वह वर्तमान क्षण को अधिक सजगता से जीने लगता है। महाकाल का अर्थ ही है वर्तमान में स्थित चेतना, क्योंकि समय के स्वामी के सामने भूत और भविष्य का कोई बंधन नहीं रहता।

उज्जैन में एक विशेष मान्यता प्रचलित है कि इस नगरी के वास्तविक राजा स्वयं महाकाल हैं। इसलिए यहां कोई भी सांसारिक राजा या उच्च पदस्थ व्यक्ति रात्रि विश्राम नहीं करता। इतिहास में कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, जिनमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा का उल्लेख किया जाता है। लोकमान्यता है कि जब उन्होंने यहां रात्रि विश्राम किया, तो शीघ्र ही उनके राजनीतिक जीवन में बड़े परिवर्तन आए। इन घटनाओं को लोग महाकाल की सर्वोच्च सत्ता के संकेत के रूप में देखते हैं। हालांकि यह आस्था का विषय है, परंतु इससे यह स्पष्ट होता है कि महाकाल को यहां सर्वोच्च शासक के रूप में माना जाता है।

महाकाल के दर्शन का सबसे गहरा लाभ मानसिक रूपांतरण है। व्यक्ति को यह बोध होता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह समय की धारा का एक भाग है। जब वह समय को शत्रु मानना छोड़ देता है और उसे एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करता है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। असफलता उसे तोड़ती नहीं, बल्कि सिखाती है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती, बल्कि कृतज्ञ बनाती है।

महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से नहीं, बल्कि पुनर्जन्म से भी है। वे संहारक हैं, परंतु वही सृजन के भी आधार हैं। जब एक अवस्था समाप्त होती है, तभी दूसरी आरंभ होती है। इस सत्य को समझकर व्यक्ति जीवन के उतार-चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करना सीखता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है।

महाकाल के मंदिर में प्रवेश करते ही जो वातावरण अनुभव होता है, वह साधारण नहीं होता। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं की आस्था एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करती है। यह ऊर्जा व्यक्ति के मन को शुद्ध करती है। वह अपने भीतर छिपे भय, क्रोध और अहंकार को धीरे-धीरे छोड़ने लगता है।

जो भक्त सच्चे मन से महाकाल का स्मरण करता है, उसके जीवन में साहस और धैर्य का संचार होता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहना सीखता है। अकाल मृत्यु का भय केवल शारीरिक अंत का भय नहीं, बल्कि असफलता, अपमान और हानि का भी भय है। महाकाल की शरण में जाकर यह समस्त भय समाप्त होने लगता है।

अंततः महाकाल का संदेश यही है कि जीवन क्षणभंगुर है, परंतु चेतना शाश्वत है। जो इस सत्य को जान लेता है, उसका भाग्य वास्तव में बदल जाता है। भाग्य का अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन है। जब भीतर संतुलन आता है, तब बाहरी परिस्थितियां भी अनुकूल होने लगती हैं। महाकाल केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि वह अनुभव हैं जो व्यक्ति को समय के पार ले जाता है। उनके दर्शन से व्यक्ति को यह अनुभूति होती है कि वह अकेला नहीं है। एक ऐसी दिव्य शक्ति उसके साथ है, जो उसे हर संकट से उबार सकती है। यही विश्वास जीवन को नई दिशा देता है।

इस प्रकार दक्षिणमुखी महाकाल के दर्शन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया हैं। जो इस अनुभव को आत्मसात कर लेता है, उसके जीवन से मृत्यु का भय हट जाता है और उसके भीतर अमरत्व की अनुभूति जन्म लेती है। यही महाकाल की कृपा है, यही उनका आशीर्वाद है, और यही वह शक्ति है जो भक्त के भाग्य को नया स्वरूप प्रदान करती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

नेशनल फाइबर स्कीम से सूरत MMF उद्योग को नई उड़ान

सूरत। देश के प्रमुख टेक्सटाइल हब सूरत में मैन-मेड फाइबर (MMF) टेक्सटाइल उद्योग के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने यूनियन बजट 2026 और बदलते वैश्विक जियोपॉलिटिकल हालातों के संदर्भ में उद्योग की संभावनाओं और चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। 'द टेक्सटाइल एसोसिएशन (इंडिया)' की साउथ गुजरात यूनिट द्वारा अडाजन में आयोजित इस सेमिनार में उद्योग जगत के वरिष्ठ विशेषज्ञों, व्यापारियों, प्रोसेसर्स और उद्यमियों ने भाग लिया। सूरत पीपुल्स बैंक के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि सरकार की नई नीतियां, विशेष रूप से नेशनल फाइबर स्कीम, और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक परिस्थितियां सूरत के MMF टेक्सटाइल उद्योग को किस दिशा में ले जा सकती हैं। सूरत लंबे समय से भारत के टेक्सटाइल उद्योग की रीढ़ रहा है। यहां हजारों की संख्या में पावरलूम, प्रोसेसिंग यूनिट्स और ट्रेडिंग कंपनियां कार्यरत हैं, जो देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए हैं। विशेष रूप से मैन-मेड फाइबर टेक्सटाइल, जिसमें पॉलिएस्टर, नायलॉन और अन्य सिंथेटिक फाइबर शामिल हैं, सूरत की पहचान बन चुका है। ऐसे में यूनियन बजट 2026 में MMF सेक्टर को नेशनल फाइबर स्कीम के तहत शामिल करना उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम माना जा रहा है।

सेमिनार के मुख्य वक्ता और चैंबर ऑफ कॉमर्स के ऑनरेरी ट्रेजरर CA मितिश मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि नेशनल फाइबर स्कीम के तहत MMF सेक्टर को शामिल करना सूरत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति भी मजबूत होगी। इस स्कीम के माध्यम से सरकार MMF सेक्टर को तकनीकी, वित्तीय और संरचनात्मक समर्थन प्रदान करेगी, जिससे उद्योग को नई तकनीकों को अपनाने और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में किए गए सुधार उद्योग के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। कच्चे माल की लागत टेक्सटाइल उद्योग के कुल उत्पादन खर्च का एक बड़ा हिस्सा होती है। जब सरकार कस्टम ड्यूटी में राहत देती है, तो इससे उत्पादन लागत में कमी आती है, जिससे उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी बनता है। इसका सीधा लाभ छोटे और मंझोले टेक्सटाइल प्रोसेसर्स को मिलेगा, जो अब कम लागत में बेहतर गुणवत्ता का उत्पादन कर सकेंगे और अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक कीमत पर बेच सकेंगे।

सूरत का टेक्सटाइल उद्योग रोजगार के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खेती के बाद टेक्सटाइल उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता माना जाता है। लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। बजट में लेबर-इंटेंसिव सेक्टर के लिए घोषित इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इससे न केवल रोजगार में वृद्धि होगी, बल्कि श्रमिकों की आय और जीवन स्तर में भी सुधार होगा। सेमिनार के दूसरे सत्र में TMMA(I) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री सचिन कुमार अरोड़ा ने वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों और उनके भारतीय टेक्सटाइल उद्योग पर प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में वैश्विक व्यापार कई जियोपॉलिटिकल चुनौतियों का सामना कर रहा है। विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक तनाव, सप्लाई चेन में बाधाएं और बदलती आर्थिक नीतियां उद्योग के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। हालांकि, इन चुनौतियों के बीच भारत के लिए नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं।

उन्होंने विशेष रूप से यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) और अमेरिका के साथ मजबूत होते व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया। इन समझौतों के माध्यम से भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक पहुंच मिलेगी और निर्यात में वृद्धि होगी। इससे भारत चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थिति में आ सकेगा। उन्होंने कहा कि यदि भारत इन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाता है, तो वह वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सकता है।

जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों का सप्लाई चेन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। ऐसे में भारत के लिए अपनी सप्लाई चेन को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर दिया जा रहा ध्यान उद्योग के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है। इससे उद्योग को स्थिरता मिलेगी और निर्यात में वृद्धि होगी।

सेमिनार में उपस्थित विशेषज्ञों ने इस बात पर भी जोर दिया कि टेक्सटाइल उद्योग को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी नवाचार को अपनाना होगा। डिजिटल तकनीकों, ऑटोमेशन और आधुनिक मशीनरी का उपयोग उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। इससे उद्योग अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। इसके साथ ही, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाना भी आवश्यक है, क्योंकि वैश्विक बाजार में पर्यावरणीय मानकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है।

सूरत का टेक्सटाइल उद्योग अपनी उद्यमशीलता और नवाचार के लिए जाना जाता है। यहां के उद्योगपति हमेशा नई तकनीकों और बाजार की मांग के अनुसार अपने उत्पादन को अनुकूलित करते रहे हैं। नेशनल फाइबर स्कीम और बजट में किए गए सुधार इस उद्योग को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे उद्योग को वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने और नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

इस सेमिनार के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि सरकार की नीतियां और वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियां सूरत के MMF टेक्सटाइल उद्योग के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यदि उद्योग इन अवसरों का सही तरीके से उपयोग करता है और तकनीकी नवाचार तथा गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान को और मजबूत कर सकता है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि नेशनल फाइबर स्कीम और बजट में किए गए सुधार सूरत के टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत हैं। यह न केवल उद्योग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे, बल्कि रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और तकनीकी विकास के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेंगे। सूरत, जो पहले से ही भारत का टेक्सटाइल पावरहाउस माना जाता है, अब MMF टेक्सटाइल के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा रहा है, और आने वाले वर्षों में इसकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है।

फ्रेट लोडिंग को गतिशील बनाने के क्रम में DRM श्री राजू भडके द्वारा GSFC का निरीक्षण

जीएनएस)। माल ढुलाई को और अधिक सशक्त एवं गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा आज, दिनांक 20 फरवरी, 2026 को Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (जीएसएफसी), बाजवा साइडिंग का दौरा किया गया। उनके इस निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्रीमती रिनी भी उपस्थित थीं।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने निरीक्षण के दौरान रेल संपर्क, माल ढुलाई अवसंरचना तथा Indian Railways और उर्वरक उद्योग के मध्य समन्वय की समीक्षा की, जिससे देश के विभिन्न राज्यों में उर्वरकों का समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित किया जा सके।

मंडल रेल प्रबंधक ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में जीएसएफसी के माल लदान प्रदर्शन की भी समीक्षा की तथा जीएसएफएसी–बाजवा साइडिंग पर अब तक के सर्वाधिक 54 रेक के मासिक लदान की उपलब्धि पर संगठन को बधाई दी। उन्होंने रेलवे एवं जीएसएफसी टीमों द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों की सराहना की।

श्री भडके ने लॉजिस्टिक प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करने, स्वचालन (ऑटोमेशन) के प्रभावी उपयोग तथा परिचालन योजना में सुधार के माध्यम से माल की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने वर्तमान 1.5 रेक प्रतिदिन की लोडिंग क्षमता को बढ़ाकर 2 रेक प्रतिदिन करने की सलाह दी, जिससे आपूर्ति श्रृंखला और अधिक सुदृढ़ हो सके। इस अवसर पर जीएसएफसी के कार्यकारी निदेशक श्री संजीव वर्मा ने कंपनी की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया तथा वडोदरा मंडल द्वारा समय पर खाली रेक उपलब्ध कराने हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बेहतर समन्वय के परिणामस्वरूप कंपनी अपनी लगभग 92 प्रतिशत उत्पादन सामग्री का परिवहन रेल मार्ग से कर सकी।

पश्चिम रेलवे कुशल माल परिवहन व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। रेलवे और उर्वरक निर्माताओं के बीच सतत समन्वय से देशभर के किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

बोईसर-पालघर स्टेशनों के बीच ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

जीएनएस)। बोईसर और पालघर स्टेशनों के बीच आर.एच. गर्डर लॉन्च करने के कार्य के लिए 21/22 फरवरी तथा 22/23 फरवरी, 2026 की मध्यरात्रि में ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 21/22 फरवरी, 2026 की मध्यरात्रि में अप एवं डाउन लाइनों पर 23:15 बजे से 02:45 बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा। इसी प्रकार 22/23 फरवरी, 2026 की मध्यरात्रि में डाउन लाइन पर 02:10 बजे से 05:25 बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा।

इन ब्लॉकों के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:-

21 फरवरी, 2026 को निरस्त रहने वाली ट्रेनें:-

1.ट्रेन संख्या 93039 विरार – दहानू रोड लोकल, जो विरार से 21:20 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।

2.ट्रेन संख्या 93042 दहानू रोड – विरार लोकल, जो दहानू रोड से 22:45 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।

रेगुलेट की जाने वाली ट्रेनें:-

1.ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस – बरौनी एक्सप्रेस, जो 21 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट होगी।

2.ट्रेन संख्या 69173 विरार – दहानू रोड मेमू, जो 21 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट होगी।

3.ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली – नंदुरबार एक्सप्रेस, जो 21 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 25 मिनट रेगुलेट होगी।

4.ट्रेन संख्या 12298 पुणे – अहमदाबाद एक्सप्रेस, जो 21 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 1 घंटा रेगुलेट होगी।

5.ट्रेन संख्या 22923 बांद्रा टर्मिनस – जामनगर एक्सप्रेस, जो 21 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 50 मिनट रेगुलेट होगी।

6.ट्रेन संख्या 19003 दादर – भुसावल एक्सप्रेस, जो 22 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 40 मिनट रेगुलेट होगी।

7.ट्रेन संख्या 19019 बांद्रा टर्मिनस – हरिद्वार एक्सप्रेस, जो 22 फरवरी, 2026 को यात्रा प्रारंभ करेगी, मार्ग में 40 मिनट रेगुलेट होगी।

मिशन जीरो स्क्रैप के तहत अहमदाबाद मंडल ने स्क्रैप बिक्री में 60 करोड़ रुपये का आंकड़ा किया पार

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने 'मिशन जीरो स्क्रैप' के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अब तक 61.53 करोड़ मूल्य की स्क्रैप सामग्री का निपटान किया है। यह उपलब्धि मिशन जीरो स्क्रैप के अंतर्गत अहमदाबाद मण्डल की अपने सभी प्रतिष्ठानों एवं इकाइयों को स्क्रैप-मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

रेलवे प्रशासन द्वारा अप्रयुक्त, परित्यक्त एवं अप्रचलित सामग्री के सुव्यवस्थित निष्पादन के माध्यम से न केवल राजस्व अर्जित किया जा रहा है, बल्कि परिसंपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन एवं स्वच्छ परिसर सुनिश्चित किया जा रहा है।

अहमदाबाद मंडल द्वारा विभिन्न प्रकार की स्क्रैप सामग्री की बिक्री की जा रही है, जिनमें स्क्रैप रेल, अन्य पी-वे (P-Way) सामग्री/स्लीपर, माइल्ड स्टील एवं कास्ट आयरन स्क्रैप, स्क्रैप बैटरियां, प्लास्टिक सामग्री, अपशिष्ट कागज, स्क्रैप लकड़ी तथा तांबा, एल्युमिनियम एवं पीतल जैसे अलौह धातु स्क्रैप शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, परित्यक्त कोच, वैगन एवं लोकोमोटिव भी नियमानुसार बेचे जाते हैं।

'मिशन जीरो स्क्रैप' के अंतर्गत यह उपलब्धि अहमदाबाद मण्डल के कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन, बेहतर हाउसकीपिंग तथा स्क्रैप सामग्री की समय पर पहचान एवं निपटान के माध्यम से संसाधनों के इष्टतम उपयोग के सतत प्रयासों को दर्शाता है।

क्रूड ऑयल वायदा में 357 रुपये का ऊछाल: सोना वायदा में 1983 रुपये और चांदी वायदा में 4958 रुपये की वृद्धि

जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 13 से 19 फरवरी के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 3395316.77 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 257070.23 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 3138234.58 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 38560 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल साप्ताहिक प्रीमियम टर्नओवर 39238.17 करोड़ रुपये का हुआ।

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 188097.59 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 153750 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 157185 रुपये और नीचे में 150730 रुपये पर पहुंचकर, 152836 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 1983 रुपये या 1.3 फीसदी के ऊछाल के साथ 154819 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 1147 रुपये या 0.92 फीसदी की तेजी के संग 126124 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 152 रुपये या 0.97 फीसदी की मजबूती के साथ सप्ताह के अंत में 15830 रुपये प्रति 1 ग्राम बंद हुआ। सोना-मिनी मार्च वायदा 152588 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 155000 रुपये और नीचे में 148678 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 2320 रुपये या 1.54 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 153008 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 154871 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 156730 रुपये और नीचे में 151080 रुपये पर पहुंचकर, 153663 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 1111 रुपये या 0.72 फीसदी की तेजी के संग 154774 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 239626 रुपये के भाव पर खूलकर, 248786 रुपये के उच्च और 226076 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 236435 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 4958 रुपये या 2.1 फीसदी की बढ़त के साथ 241393 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 1471 रुपये या 0.6 फीसदी बढ़कर 244795 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1245 रुपये या 0.51 फीसदी की तेजी के संग सप्ताह के अंत में 244712 रुपये प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 39724.47 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 46.05 रुपये या 3.82 फीसदी औंधकर 1160.25 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 65 पैसे या 0.2 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ सप्ताह के अंत में 324 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा सप्ताह के अंत में 1.5 रुपये या 0.49 फीसदी घटकर 306.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा फरवरी वायदा 15 पैसे या 0.08 फीसदी के सुधार के साथ 187.95 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 257070 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 3138234 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 188097 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 38560 पॉइंट के स्तर पर

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 29231.34 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 5699 रुपये के भाव पर खूलकर, 6097 रुपये के उच्च और 5628 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 357 रुपये या 6.26 फीसदी की मजबूती के साथ 6058 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 357 रुपये या 6.26 फीसदी की तेजी के संग 6060 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सप्ताह के आरंभ में 279.4 रुपये के भाव पर खूलकर, 283.7 रुपये के उच्च और 261.8 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 284.2 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 12.8 रुपये या 4.5 फीसदी लुढ़ककर 271.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा सप्ताह के अंत में 12.7 रुपये या 4.47 फीसदी औंधकर 271.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर बंद हुआ।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा सप्ताह के आरंभ में 965 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 11.5 रुपये या 1.19 फीसदी गिरकर 955.1 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 102177.14 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 85920.45 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 34173.41 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 2584.37 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 184.10 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2693.38 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 12256.26 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 16884.79 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 13.18 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सप्ताह के अंत में सोना के वायदाओं में 7394 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 40068 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 12721 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 148384 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 27368 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 5957 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 6567 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 24881 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14967 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 10100 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा 38560 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 38560 के उच्च और 38560 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 117 पॉइंट बढ़कर 38560 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।

फियो ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत सात नए उपायों का स्वागत किया; कहा कि इन उपायों से एमएसएमई की कॉम्पिटिटिवनेस और ग्लोबल मार्केट एक्सेस बढ़ेगी

जीएनएस)। नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स (फियो) ने माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (ईपीएम) के तहत सात नए उपाय शुरू करने का स्वागत किया है, और इस पहल को एमएसएमई की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने और भारत की ग्लोबल मार्केट उपस्थिति को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा संरचनागत कदम बताया है।

फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि यह मिशन उन बुनियादी रुकावटों — क्रेडिट की ज़्यादा लागत, अलग-अलग तरह के ट्रेड फाइनेंस तक सीमित एक्सेस, अनुपालन का बोझ, लॉजिस्टिक्स की कमियां और जानकारी की कमी को दूर करता है जो एमएसएमई निर्यात वृद्धि को रोकती हैं। 'निर्यात प्रोत्साहन' और 'निर्यात दिशा' के तहत नए शुरू किए गए उपाय का लक्ष्य पारंपरिक प्रोत्साहन से आगे बढ़ना और सिस्टेमैटिक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने पर फोकस करना है।

2.75 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन के साथ एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट फैसिलिटी और बढ़े हुए गारंटी मैकेनिज्म जैसे वैकल्पिक ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सपोर्ट से वर्किंग कैपिटल का दबाव काफी कम हो जाएगा। फाइनेंस की कम लागत और बेहतर तरलता चक्र एमएसएमई को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग करने, बड़े ऑर्डर लेने और ओवरसीज बायर्स के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी मजबूत करने में मदद करेंगे। शेयर्ड-रिस्क क्रेडिट मैकेनिज्म से भी पहली बार निर्यात करने वालों को बढ़ावा मिलने और प्रोडक्ट तथा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अनुपालन मोर्चे पर, टीआरएसीई (ट्रेड रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन एंड कम्प्लायंस इनेबलमेंट) टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन कॉस्ट को कुछ हद तक रीइम्बर्स करेगा, जिससे एमएसएमई को तेजी से सख्त होते ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने और हाई-वैल्यू रेगुलेटेड मार्केट तक पहुंचने में मदद मिलेगी। फ्लो (फैसिलिटेटिंग लॉजिस्टिक्स, ओवरसीज वेयरहाउसिंग एंड फुलफिलमेंट), जिसमें दुबई में भारत मार्ट जैसे ओवरसीज वेयरहाउसिंग इनिशिएटिव्स के लिए सहायता शामिल है, निर्यातकों को डेस्टिनेशन मार्केट्स के करीब इन्वेंट्री रखने, डिलीवरी टाइमलाइन कम करने और ई-कॉमर्स और फास्ट-मूविंग सेगमेंट्स में ज्यादा प्रभावी ढंग कम्पीट करने में मदद करेगा। एलआईएफटी (लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट) दूर-दराज के क्षेत्रों में मौजूद एक्सपोर्टर्स के लिए फ्रेट से जुड़े नुकसान को कम करने में मदद करेगा, जिससे रीजनल एक्सपोर्ट ग्रोथ ज़्यादा संतुलित होगी। इनसाइट (इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर ट्रेड इंटेलिजेंस एंड फैसिलिटेशन) बेहतर मार्केट इंटेलिजेंस और डिमांड मैपिंग के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट और क्लस्टर-लेवल के निर्यात इकोसिस्टम को मज़बूत करेगा, जिससे एमएसएमई मार्केट में डायवर्सिफाई कर सकें और कंसंट्रेशन रिस्क कम कर सकें।

श्री रल्हन ने बताया कि तीन खास उपाय — मार्केट एक्सेस सपोर्ट, प्री- और पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन, और एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए कोलैटरल सपोर्ट — पहले से ही लागू हैं, जिससे मिशन के तहत एक्टिव इंटरवेंशन की कुल संख्या दस हो गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि इन उपायों से ट्रांज़ैक्शन लागत कम होगी, फाइनेंस तक पहुंच बेहतर होगी, कम्प्लायंस रेडीनेस मज़बूत होगी और भारतीय एमएसएमई का ग्लोबल वैल्यू चेन में एकीकरण और गहरा होगा।

श्री रल्हन ने कहा, "एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लंबे समय की निर्यात क्षमता बनाने की दिशा में एक अहम बदलाव प्रदर्शित करता है। यह एमएसएमई को न केवल ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा लेने, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला करने, आगे बढ़ाने और अपनी मौजूदगी बनाए रखने में भी मदद करता है।"

फियो ने सरकार, एक्जिम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और विदेश में भारतीय मिशन के साथ मिलकर काम करने का अपना वादा दोहराया, ताकि असरदार तरीके से लागू किया जा सके और खासकर जिला स्तर पर ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, ताकि भारत को दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी निर्यात पावरहाउस बनने में मदद मिल सके।

रविवार, 22 फरवरी, 2026 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं

पश्चिम रेलवे का वसई रोड एवं विरार स्टेशनों के बीच रात्रिकालीन ब्लॉक

जीएनएस)। रेलपथ, सिगनलिंग तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा वसई रोड एवं विरार स्टेशनों के बीच शनिवार/रविवार अर्थात 21/22 फरवरी, 2026 की मध्यरात्रि के दौरान अप एवं डाउन धीमी लाइनों पर 00.15 बजे से 04.15 बजे तक चार घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बोरीवली एवं दहिसर स्टेशनों के बीच सभी लाइनों पर 02.10 बजे से 04.10 बजे तक नए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) के गर्डर लॉन्चिंग हेतु एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान धीमी लाइनों की सभी उपनगरीय ट्रेनों को वसई रोड एवं विरार स्टेशनों के बीच फास्ट लाइनों पर चलाया जाएगा। बोरीवली एवं दहिसर के बीच एफओबी के गर्डर लॉन्चिंग कार्य के कारण कुछ उपनगरीय तथा मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

1)ट्रेन संख्या 19038 बरौनी–बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस को विरार एवं भायंदर स्टेशनों के बीच 01 घंटा रेगुलेट होगी।

2)ट्रेन संख्या 22946 ओखा–मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल को विरार एवं भायंदर स्टेशनों के बीच 45 मिनट रेगुलेट होगी।

3)ट्रेन संख्या 22904 भुज–बांद्रा टर्मिनस एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को सूरत एवं विरार स्टेशनों के बीच 20 मिनट रेगुलेट होगी।

4)ट्रेन संख्या 90006 विरार–चर्चगेट लोकल, जो विरार से 03.25 बजे प्रस्थान करती है, को विरार से 15 मिनट विलंब से चलाया जाएगा।

5)ट्रेन संख्या 90018 विरार–चर्चगेट लोकल, जो विरार से 03.40 बजे प्रस्थान करती है, को विरार से 15 मिनट विलंब से चलाया जाएगा।

ब्लॉक के दौरान कुछ उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है।

इसलिए, पश्चिम रेलवे उपनगरीय खंड पर रविवार, 22 फरवरी, 2026 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

केम-ओ-क्लेव 2.0: आई.आई. सी. एच. ई-पी. डी. ई. यू ने नवाचार और स्थिरता के माध्यम से उद्योग–शैक्षणिक सहयोग को सशक्त बनाया

जीएनएस)। गांधीनगर : पंडित दीनदयाल एनर्जी विश्वविद्यालय (PDEU) के रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग ने आई.आई. सी. एच. ई छात्र चैप्टर के सहयोग से सफलतापूर्वक केम-ओ-क्लेव 2.0: एक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार, स्थिरता और उद्योग–शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को ज्ञान-विनिमय (आदान प्रदान) तथा व्यावसायिक विकास के लिए एक साझा मंच प्रदान किया गया।

"सक्षम" केंद्रीय थीम के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य ऐसे दक्ष और भविष्य के लिए तैयार अभियंताओं का निर्माण करना था, जो बदलती औद्योगिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रभावी समाधान कर सकें। कार्यक्रम की शुरुआत पंजीकरण और अतिथियों के स्वागत से हुई, जिसके पश्चात पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह आयोजित किया गया, जो ज्ञान और विवेक की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है।

उद्घाटन सत्र में विश्वविद्यालय के नेतृत्व और संकाय सदस्यों द्वारा विशिष्ट अतिथियों का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रो. राजेश पटेल एवं रजिस्ट्रार श्री राकेश श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि डॉ. रक्ष वीर जसरा (सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, रिलायंस) का स्वागत किया। डॉ. स्वप्निल धरास्कर ने श्री श्रेयान गुप्ता (निदेशक, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड) का स्वागत किया, जबकि रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख डॉ. आशीष उन्नारकट ने श्री आलोक आर्य (प्रेसिडेंट लीगल एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड) का स्वागत किया। डॉ. शुभंकर रॉय ने श्री विजु विश्वनाथ (चीफ मैनेजर, इंडियन ऑयल लुब्रिकेंट्स विभाग, IOCL) का अभिनंदन किया।

समारोह को आई.आई. सी. एच. ई-पी. डी. ई. यू. के अध्यक्ष श्री मिलाप जोगीदास के संबोधन ने और समृद्ध किया। उन्होंने तकनीकी रूप से सक्षम, नैतिक रूप से उत्तरदायी और नवाचार-उन्मुख अभियंताओं के निर्माण में पेशेवर संगठनों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उद्घाटन व्याख्यानों में आधुनिक रासायनिक अभियांत्रिकी की उभरती प्राथमिकताओं—विशेष रूप से स्थिरता, हरित रसायन और तकनीकी नवाचार—पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि केम-ओ-क्लेव 2.0: जैसे मंच अकादमिक शिक्षा और वास्तविक औद्योगिक अभ्यास के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को व्यावहारिक चुनौतियों और उद्योग की अपेक्षाओं की स्पष्ट समझ मिलती है।

डॉ. स्वप्निल धरास्कर ने वर्तमान तीव्र परिवर्तनशील इंजीनियरिंग परिदृश्य में अंतःविषय सहयोग और निरंतर सीखने के महत्व पर मूल्यवान विचार साझा किए। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण डॉ. राकेश वीर बसरा (सीनियर वाइस प्रेसिडेंट – रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स R&D, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड) का प्लेनरी व्याख्यान रहा। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा पर चर्चा करते हुए ऊर्जा को आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति का गुणक बताया। उन्होंने उन्नत प्लास्टिक रीसाइक्लिंग तकनीकों, विशेषकर पी. ई . टी अपशिष्ट की ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, को परिपत्र अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि स्थिरता को केवल अनुपालन तक सीमित न रखकर औद्योगिक डिज़ाइन और संचालन की मूल दर्शन बनाना आवश्यक है।

एक अन्य प्रेरक सत्र में श्री श्रेयान गुप्ता ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और उद्यमिता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने विद्यार्थियों को परंपरागत करियर विकल्पों से आगे बढ़कर नवाचार-आधारित सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया तथा अनुकूलनशीलता और सिस्टम थिंकिंग को आज के वैश्विक परिवेश में आवश्यक गुण बताया।

श्री विजु विश्वनाथ ने "आदर्श अभियंता की यात्रा" विषय पर एक संवादात्मक सत्र संचालित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को तकनीकी दक्षता के साथ-साथ संचार कौशल, नैतिक मूल्यों और आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

अंततः, प्रभावशाली वक्ताओं और सार्थक तकनीकी चर्चाओं के साथ केम-ओ-क्लेव 2.0: ने उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग के महत्व को और अधिक सुदृढ़ किया। इस आयोजन ने प्रतिभागियों को पारंपरिक सीमाओं से आगे सोचने और रासायनिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में एक अधिक स्थायी और नवोन्मेषी भविष्य की दिशा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

पश्चिम रेलवे चलाएगी छह जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें,राजकोट - महबूबनगर स्पेशल के फेरे बढ़ाए गए

जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा तथा होली पर्व के दौरान यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे विशेष किराए पर छह जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09075/09076 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09075 मुंबई सेंट्रल – काठगोदाम स्पेशल प्रत्येक बुधवार को 10:55 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर अगले दिन 14:30 बजे काठगोदाम पहुँचेगी। यह ट्रेन 25 फरवरी, 2026 से 25 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09076 काठगोदाम – मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 17:30 बजे काठगोदाम से प्रस्थान कर अगले दिन 21:00 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। यह ट्रेन 26 फरवरी, 2026 से 26 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, हिण्डौन सिटी, भरतपुर, अछनेरा, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बदायूं, बरेली जं., बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेड़ी, किच्छा, लालकुआँ एवं हल्द्वानी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09185/09186 मुंबई सेंट्रल – कानपुर अनवरगंज साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09185 मुंबई सेंट्रल – कानपुर अनवरगंज स्पेशल प्रत्येक रविवार को 10:55 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर अगले दिन 15:35 बजे कानपुर अनवरगंज पहुँचेगी। यह ट्रेन 22 फरवरी, 2026 से 29 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज – मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक सोमवार को कानपुर अनवरगंज से 18:25 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 22:30 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 फरवरी, 2026 से 30 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, वडोदरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, मथुरा कैंट, हाथरस सिटी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज एवं बिल्हौर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09185 का सूरत स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 09023/09024 बांद्रा टर्मिनस – पालिताना साप्ताहिक स्पेशल (02 फेरे)

ट्रेन संख्या 09023 बांद्रा टर्मिनस – पालिताना स्पेशल 27 फरवरी, 2026 (शुक्रवार) को 21:45 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान कर अगले दिन 12:00 बजे पालिताना पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09024 पालिताना – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 01 मार्च, 2026 (रविवार) को 20:00 बजे पालिताना से प्रस्थान कर अगले दिन 12:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, बोटाद, धोला, सोनगढ़ एवं सिहोर स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 03418/03417 उधना – मालदा टाउन साप्ताहिक स्पेशल (08 फेरे)

ट्रेन संख्या 03418 उधना – मालदा टाउन स्पेशल प्रत्येक सोमवार को 12:30 बजे उधना से प्रस्थान कर बुधवार को 05:55 बजे मालदा टाउन पहुँचेगी। यह ट्रेन 02 मार्च से 23 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 03417 मालदा टाउन – उधना स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 12:15 बजे मालदा टाउन से प्रस्थान कर सोमवार को 02:15 बजे उधना पहुँचेगी। यह ट्रेन 28 फरवरी, 2026 से 21 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में चलथान, व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, डोंडाईचा, अमलनेर, भुसावल, इटारसी, पिपरिया, मदन महल, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, तिलैया, नवादा, शेखपुरा, किऊल, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, कहलगांव, साहिबगंज, बरहरवा एवं न्यू फरक्का स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

5. ट्रेन संख्या 09425/09426 साबरमती – हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09425 साबरमती – हरिद्वार स्पेशल प्रत्येक सोमवार को 18:45 बजे साबरमती से प्रस्थान कर अगले दिन 20:30 बजे हरिद्वार पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 फरवरी, 2026 से 23 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09426 हरिद्वार – साबरमती स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को हरिद्वार से 21:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 22:30 बजे साबरमती पहुँचेगी। यह ट्रेन 24 फरवरी, 2026 से 24 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, जवाई बांध, फालना, रानी, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली कैंट, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर एवं रुड़की स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

6. ट्रेन संख्या 09309/09310 इंदौर – हजरत निजामुद्दीन द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (20 फेरे)

ट्रेन संख्या 09309 इंदौर – हजरत निजामुद्दीन स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार एवं रविवार को 17:00 बजे इंदौर से प्रस्थान कर अगले दिन 05:00 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुँचेगी। यह ट्रेन 22 फरवरी, 2026 से 27 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09310 हजरत निजामुद्दीन – इंदौर स्पेशल प्रत्येक शनिवार एवं सोमवार को हजरत निजामुद्दीन से 08:20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 21:00 बजे इंदौर पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 फरवरी, 2026 से 28 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में देवास, उज्जैन, नागदा, शामगढ़, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर एवं मथुरा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09575/09576 राजकोट – महबूबनगर साप्ताहिक स्पेशल का विस्तार

ट्रेन संख्या 09575 राजकोट – महबूबनगर स्पेशल को 30 मार्च, 2026 तक तथा ट्रेन संख्या 09576 महबूबनगर - राजकोट स्पेशल को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाया गया है।

मातृभाषा के गौरव गान के साथ अन्य भाषाओं के प्रति आदर ही हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- मुख्यमंत्री ने विश्व मातृभाषा दिवस की पूर्व संध्या पर गांधीनगर में गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित मातृभाषा महोत्सव अंतर्गत साहित्य गौरव पुरस्कार प्रदान किए
- वर्ष 2024 का साहित्य गौरव पुरस्कार गुजराती भाषा के लिए श्री प्रवीण दर्जी को तथा कच्छी भाषा के लिए श्री मावजी महेश्वरी को प्रदान किया गया
- युवा गौरव पुरस्कार अंतर्गत गुजराती भाषा साहित्य के लिए श्री अजय सोनी को तथा कच्छी भाषा साहित्य के लिए श्री दीपक नंदा को वर्ष 2024 के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया
- मुख्यमंत्री का 'विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात' के निर्माण से लीड लेने में मातृभाषा एवं संस्कृति के जतन-संवर्धन से योगदान देने का आह्वान

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने मातृभाषा दिवस के गरिमामय समारोह में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि मातृभाषा के गौरव गान के साथ अन्य भाषाओं के प्रति आदर ही हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमारी मातृभाषा 'अ' से शुरू होकर सबसे शीर्ष पर 'ज्ञ' यानी ज्ञान तक विस्तृत है। हृदय के भाव एवं संवेदनाओं को भाषा से प्रकट करने का हमारा प्रयास मातृभाषा के ऐसे समृद्ध ज्ञान द्वारा ही व्यक्त हो सकता है। उन्होंने जोड़ा कि हमारी भाषा एवं संस्कृति को जीवंत रखकर आगामी पीढ़ी तक पहुँचाना समय की मांग है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल विश्व मातृभाषा दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को गांधीनगर में गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा मातृभाषा महोत्सव अंतर्गत आयोजित साहित्य गौरव पुरस्कार समारोह के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। समारोह में युवा, सेवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ राज्य मंत्री डॉ. जयराम गामित भी उपस्थित थे। 'माँ, मातृभूमि तथा मातृभाषा का कोई सानी नहीं है।' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभाषा का गौरव करने वाला कोई भी व्यक्ति उनके लिए गौरवरूपी है।

इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2024 का साहित्य गौरव पुरस्कार गुजराती भाषा के लिए श्री प्रवीण दर्जी को तथा कच्छी भाषा के लिए श्री मावजी महेश्वरी को प्रदान किया। गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा युवा लेखकों-साहित्यकारों को दिए जाने वाले युवा गौरव पुरस्कार अंतर्गत श्री अजय सोनी तथा श्री दीपक नंदा को वर्ष 2024 के क्रमशः गुजराती तथा कच्छी भाषा साहित्य के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने मातृभाषा को सामूहिक अस्तित्व तथा स्वाभिमान का प्रतीक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों में ऐसा ही स्वाभिमान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व तथा विरासतों व संस्कृति के पुनरुत्थान से जगाया है।

श्री पटेल ने विकसित भारत@2047 के प्रधानमंत्री के विजन में भी संस्कृति, भाषा एवं ज्ञान परंपरा के विशेष स्थान का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने सभी मातृभाषाप्रेमियों, साहित्यप्रेमियों, लेखकों, रचयिताओं तथा प्रबुद्ध नागरिकों का आह्वान किया कि वे विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण से लीड लेने में मातृभाषा तथा संस्कृति के जतन-संवर्धन से योगदान दें।

इस अवसर पर गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री भाग्येश झा ने मुख्यमंत्री सहित सभी उपस्थित महानुभावों का शब्दों से स्वागत किया। समारोह में अकादमी द्वारा एक साथ लगभग 51 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।

इस कार्यक्रम में खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विभाग के सचिव डॉ. राहुल गुप्ता, गुजरात साहित्य अकादमी के महामात्र डॉ. जयेन्द्रसिंह जादव, सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री माधव रामानुज, संगीतकार श्री श्यामल-सौमिल मुनशी तथा सुश्री आरती मुनशी, साहित्यकार श्री तुषारभाई शुक्ल एवं लोक गायक श्री कीर्तिदान गढवी सहित बड़ी संख्या में साहित्यकार, भाषाप्रेमी व साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे चलाएगी साबरमती और हरिद्वार के बीच होली स्पेशल ट्रेन

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी होली फेस्टिवल के दौरान, यात्रियों की मांग व सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती-हरिद्वार के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, साथ ही असारवा से आगरा केंट के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इन विशेष ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09425/09426 साबरमती-हरिद्वार-साबरमती स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09425 साबरमती-हरिद्वार स्पेशल 23 फरवरी और 02,09,16,23 मार्च 2026 को साबरमती से 18.45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 20.30 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09426 हरिद्वार-साबरमती स्पेशल 24 फरवरी और 03,10,17,24 मार्च 2026 को हरिद्वार से 21:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 22:30 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबूरोड, पिंडवाड़ा, जवाई बांध, फालना,रानी, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर,

गांधीनगर-जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गाँव, दिल्ली केंट, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर एवं रुड़की स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 01920/01919 असारवा-आगरा केंट-असारवा स्पेशल (60 फेरे)

ट्रेन संख्या 01920 असारवा-आगरा केंट स्पेशल 19 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक (मंगलवार और बुधवार को छोडकर) असारवा से प्रतिदिन 14.50 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07.45 बजे आगरा केंट पहुंचेगी। इस तरह ट्रेन संख्या 01919 आगरा केंट-असारवा स्पेशल 18 फरवरी से 29 मार्च 2026 तक (सोमवार और मंगलवार को छोडकर) आगरा केंट से प्रतिदिन 18.10 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11.10 बजे असारवा पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर, सेमारी, जावर, उदयपुर सिटी, राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, मांडल गढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, रूपबास और फतेहपुर सीकरी स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेन संख्या 09425 की बुकिंग 21 फरवरी, 2026 से यात्री आरक्षण केन्द्रों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी तथा ट्रेन संख्या 01920 की बुकिंग शुरू है। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

"फाल्गुन फेरी" के उपलक्ष्य में 01 मार्च को पालीताना से बान्द्रा के लिए चलेगी विशेष ट्रेन, टिकट बुकिंग 21 फरवरी से शुरू होगी

जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा तथा "फाल्गुन फेरी" के अवसर पर पालीताना जैन मंदिर में होने वाली क्षद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा विशेष किराये पर पालीताना और बान्द्रा टर्मिनस के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संचालन विवरण:

बान्द्रा टर्मिनस से पालीताना के लिए चलने वाली बान्द्रा-पालीताना सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (09023) दिनांक 27 फरवरी, 2026 (शुक्रवार) को बान्द्रा टर्मिनस से रात्रि 21.45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन दोपहर 12.00 बजे पालीताना पहुंचेगी।

इसी प्रकार वापसी में पालीताना-बान्द्रा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

(09024) दिनांक 01 मार्च, 2026 (रविवार) को पालीताना से रात्रि 20.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन दोपहर 12.00 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सिहोर (गुजरात), सोनगढ़, धोला, बोटाद, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी एवं बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास के कोच उपलब्ध रहेंगे।

बुकिंग संबंधी जानकारी :

ट्रेन संख्या 09023 एवं 09024 की बुकिंग दिनांक 21 फरवरी, 20206 (शनिवार) से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर शूरू होगी। यात्री ट्रेन के परिचालन समय, ठहराव एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने लापता व्यक्तियों की बढ़ती संख्या और व्यवस्था की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की

जीएनएस)। (छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

देश भर में हर साल बड़ी संख्या में लोग लापता होते हैं और यह सिलसिला जारी है। इनमें से अधिकतर बच्चे, महिलाएं और लड़कियां होती हैं। इस साल जनवरी के पहले सप्ताह में अकेले दिल्ली से 800 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर ने एक बार फिर इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया है। फिर भी, हैरानी की बात यह है कि इस आपराधिक समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस राष्ट्रीय प्रयास नहीं किया गया है। लापता व्यक्तियों का राज्यवार विश्लेषण भी बहुत कम उपलब्ध है। अब तक कितने लोग मिले हैं? और इन मामलों के पीछे कौन है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ज़रा सोचिए, अगर कुछ ही दिनों में अकेले दिल्ली से 800 लोग लापता हो गए, तो पूरे देश से कितने लोग लापता हुए होंगे?

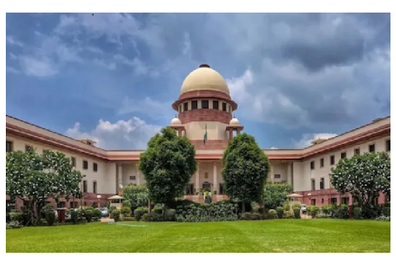

शून्य त्रुटि एजेंसी

इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से देश के विभिन्न हिस्सों में लापता बच्चों की घटनाओं के पीछे किसी विशेष समूह की संलिप्तता की जांच करने को कहा है। इसके लिए, न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऐसे मामलों की संख्या और सभी राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने का निर्देश दिया है। जब सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है, तो क्या केंद्र सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि वह ऐसे कदम उठाए? यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देशभर से लापता बच्चों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, जहां सभी राज्य ऐसी घटनाओं का विवरण जमा कर सकते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया में सरकारी तंत्र की उदासीनता स्पष्ट है। केंद्र सरकार ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार किया था कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और संबंधित कार्यवाही से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। लेकिन केंद्र सरकार अदालत में ऐसा जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीबी) की रिपोर्ट से इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि 2023 में देशभर में 8 लाख से अधिक लोग लापता हुए। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है। गुजरात में भी यह समस्या गंभीर है, जहां शहरों से लेकर गांवों तक लोगों के लापता होने की खबरें लगातार आती रहती हैं। खासकर छोटे बच्चों या लड़कियों की संख्या अधिक है। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राज्य अपनी जिम्मेदारी को समझे और लापता व्यक्तियों के मामलों में तत्काल कार्रवाई करे। यदि कोई लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों को प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और प्रणाली को उसकी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा, यह चक्र चलता रहेगा और प्रणाली गहरी नींद में सोई रहेगी।